• कार्यक्रम...

आधार पर कार्यशाला

शिमला : भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) के क्षेत्रीय कार्यालय चंडीगढ़ द्वारा हिमाचल प्रदेश में आधार (एए्डीएचएएआर) और इससे जुड़े विभिन्न विषयों पर विस्तृत चर्चा के लिए कार्यशाला का आयोजन किया। कार्यशाला का शुभारंभ भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण, क्षेत्रीय कार्यालय चंडीगढ़ की उप-महानिदेशक भावना गर्ग ने किया। भावना गर्ग ने आधार के उपयोग के विभिन्न पहलुओं की जानकारी देते हुए कहा कि आधार पर क्यूआर कोड का उपयोग इसकी प्रमाणिकता की जांच के लिए किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश 0-5 वर्ष आयु वर्ग के आधार नामांकन के लिए देश में पहले स्थान पर है। उन्होंने बच्चों के नामांकन के लिए विभिन्न विभागों के एकीकरण की आवश्यकता पर बल दिया, जिसमें स्वास्थ्य विभाग को बाल नामांकन टेबलेट प्रदान करना और स्कूलों को नामांकन किट की सुविधा प्रदान करना शामिल है।सचिव प्रियतु मंडल ने कहा कि कानूनी ढांचे को व्यवहारिक कार्यान्वयन रणनीतियों के साथ जोड़कर यह सुनिश्चित करने के प्रयास किए जा रहे हैं कि आधार शासन और जन कल्याण के लिए एक मजबूत उपकरण के रूप में निरंतर अहम भूमिका निभाए।

एनएच की मुरम्मत

शिमला : लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण सड़क, परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय तथा लोक निर्माण विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक बैठक की अध्यक्षता की। यह प्रारंभिक बैठक 16 जुलाई, 2024 को केन्द्रीय सड़क, परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के पास हिमाचल प्रदेश के राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं से संबंधित मुद्दों पर चर्चा करने के लिए आयोजित की गई। लोक निर्माण मंत्री ने राष्ट्रीय राजमार्गों की प्रगति कार्यों की समीक्षा की और अधिकारियों को निर्देश दिए कि जो राष्ट्रीय राजमार्ग क्षतिग्रस्त हैं, उन्हें तुरंत ठीक करवाया जाए। उन्होंने भुभू जोत टनल के निर्माण कार्यों को भी शीघ्र पूर्ण करवाने के निर्देश दिए, ताकि इसे जन कल्याण के लिए शीघ्र समर्पित किया जा सके।भारत सरकार के स ?क, परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के साथ होने वाली बैठक में प्रदेश के विभिन्न राजमार्गों और परियोजनाओं पर की जाने वाली कार्रवाई एवं उनसे जुड़ी समस्याओं पर चर्चा की जाएगी।

• वाक युद्ध...

नेगी का जयराम पर वार

शिमला : हिमाचल में केंद्रीय जांच एजेंसियों की ओर से की गई कर्रवाई को प्रदेश सरकार ने दुर्भाग्य पूर्ण बताया है। शिमला में बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा हिमाचल को बदनाम करने के लिए भाजपा केंद्रीय जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में तीन विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के दौरान ईडी और इन्कम टैक्स की रेड दुर्भाग्यपूर्ण है।

पूर्व में चुनाव के दौरान कभी भी जांच एजेंसियों इस तरह कार्रवाई नहीं की है, लेकिन प्रदेश के इतिहास में पहली बार इस तरह की रेड हुई है, जिससे हिमाचल बदनाम हुआ है। उन्होंने कहा उपचुनाव में प्रदेश सरकार के खिलाफ भाजपा के पास कोई मुद्दा नहीं था इसलिए रेड डलवाकर चुनाव को प्रभावित करने का प्रयास किया गया।

जांच एजेंसी लेकर आए जयराम ठाकुर : जगत सिंह नेगी ने कहा नादौन और हमीरपुर में ईडी ने रेड कर लोगों का उत्पीड़न किया है, ताकि किसी न किसी तरह से जबरन मुख्यमंत्री का नाम इस मामले में घसीटा जा सके। उन्होंने नेता प्रतिपक्ष जयराम पर दिल्ली जाकर हिमाचल के लिए कोई पैकेज लाने की पैरवी करने के बजाय प्रदेश को बदनाम करने के लिए जांच एजेंसियों लाने का आरोप लगाया।

नेगी कहा प्रदेश में जब भाजपा की सरकार थी तो पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर केंद्र और राज्य में डबल इंजन की सरकार होने का दम भरते थे, लेकिन इसके बावजूद वह प्रदेश के लिए कुछ भी नहीं कर पाए. उन्होंने कहा नेता प्रतिपक्ष ने तीन निर्दलीय विधायकों को भ्रमित कर प्रदेश में उपचुनाव थोपा है और अब इस तरह के षड्यंत्र रचकर जांच एजेंसियों का दुरुपयोग भी करवा रहे हैं।

जगत सिंह नेगी ने कहा भाजपा के नेता कह रहे हैं कि केंद्रीय जांच एजेंसियों की कार्रवाई का चुनाव से कोई संबंध नहीं है, लेकिन भाजपा को ये भी बताना चाहिए कि ये रेड अगर गैर राजनीतिक है तो उपचुनाव के दौरान इस तरह की कार्रवाई कहां तक तर्कसंगत है। उन्होंने कहा भाजपा ने रेड डलवाकर चुनाव को प्रभावित करने का प्रयास किया है जिसमें वे सफल नहीं हो पाएंगे. नेगी ने कहा उपचुनाव में देहरा से भाजपा प्रत्याशी होशियार सिंह ने गोली चलाने की बात कहकर प्रदेश के शांतिपूर्ण माहौल को खराब करने का प्रयास किया है।

एचआरटीसी कर्मचारियों से 67 लाख रिकवरी

• पंकज/शिमला

राज्य सरकार के उपक्रम हिमाचल प्रदेश पथ परिवहन निगम (एचआरटीसी) ने अपने कर्मचारियों से 67 लाख रुपये वसूले हैं। निगम के सभी चालकों, परिचालकों और मैकेनिकल स्टाफ के वेतन से 748 रुपये काटे गए हैं। कर्मचारी इसका विरोध कर रहे हैं।

दरअसल, एचआरटीसी अपने कर्मचारियों को हर साल दो वर्दी देता है। इसके एवज में उन्हें 2000 रुपये भत्ता दिया जाता है। लेकिन इस साल वर्दी खरीदने से पहले एचआरटीसी कर्मचारियों ने तर्क दिया कि कपड़ा महंगा हो गया है, इसलिए वर्दी भत्ता बढ़ाया जाना चाहिए।

कर्मचारियों ने पिछले साल खरीदी गई वर्दी की गुणवत्ता पर भी सवाल उठाए थे। इसलिए इस साल वर्दी खरीदने से पहले यूनियन पदाधिकारियों की ड्रेस खरीद समिति के साथ बैठक हुई। इस बैठक की कार्यवाही विधिवत तैयार की गई, जिस पर कर्मचारी नेताओं के हस्ताक्षर हैं।

बैठक में लिए गए निर्णय के बाद इस बार एचआरटीसी ने 2000 रुपये की जगह 2748 रुपये की ड्रेस खरीदकर अपने कर्मचारियों को दी। इस बार जब जून महीने का वेतन आया तो सभी कर्मचारियों के वेतन में 748 रुपये कम थे। इसके बाद सभी कर्मचारी परेशान हो गए। जब एचआरटीसी प्रबंधन से इस बारे में पूछा गया तो पता चला कि वर्दी के पैसे काट लिए गए हैं।

इससे कर्मचारी भड़क गए हैं। मगर खुलकर बोल भी नहीं पा रहे, क्योंकि इनके कर्मचारी नेताओं ने क्वालिटी ड्रेस खरीदने की बात मीटिंग में कही थी। बोर्ड प्रबंधन ने क्वालिटी ड्रेस तो दे दी, लेकिन इनका वर्दी भत्ता नहीं बढ़ाया गया। एचआरटीसी में यह ड्रेस फील्ड स्टाफ को दी जाती है। इनकी संख्या 8500 से ज्यादा है। सभी कर्मचारियों से रिकवरी की गई है।

एचआरटीसी के प्रबंध निदेशक रोहन चंद ठाकुर ने बताया, निगम ने कर्मचारियों के लिए अच्छी क्वालिटी की ड्रेस खरीदी है। यह कर्मचारियों के साथ हुई मीटिंग में तय हुआ था। इसमें सभी यूनियन के पदाधिकारी मौजूद थे। सभी की सहमति के बाद ही वर्दी खरीदी है।

बैठक में लिए गए निर्णय के बाद इस बार एचआरटीसी ने 2000 रुपये की जगह 2748 रुपये की ड्रेस खरीदकर अपने कर्मचारियों को दी।

इस बार जब जून महीने का वेतन आया तो सभी कर्मचारियों के वेतन में 748 रुपये कम थे। इसके बाद सभी कर्मचारी परेशान हो गए। जब एचआरटीसी प्रबंधन से इस बारे में पूछा गया तो पता चला कि वर्दी के पैसे काट लिए गए हैं...

रोहित ठाकुर बोले-4350 स्कूलों में नए नियुक्त शिक्षकों की तैनाती प्राथमिकता

शिमला : हिमाचल प्रदेश के शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा कि शिक्षा क्षेत्र को सुदृढ़ करने के लिए आज समय के अनुसार बदलाव की आवश्यकता है। शिक्षा मंत्री ने गुरुवार को शिमला में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि करीब 2200 शिक्षकों की बैचवाइज भर्ती की जा रही है और जल्द इनकी तैनाती होगी। कहा कि शिक्षकों की तैनाती के लिए भी पैरामीटर तय किए गए हैं। राज्य में बिना शिक्षक 350 स्कूल चल रहे हैं। 3200 स्कूल एक शिक्षक के सहारे हैं और करीब 800 स्कूल ऑफ एक्सीलेंस हैं। इन स्कूलों में शिक्षकों की तैनाती प्राथमिकता रहेगी। कहा कि सरकार चाहती है कि प्री प्राइमरी स्कूल जल्द शुरू किए जाए। इसके लिए करीब 6100 एनटीटी शिक्षक भर्ती किए जाएंगे।

कम संख्या वाले स्कूलों को मर्ज करने के सवाल पर रोहित ने कहा कि वित्त आयोग के हिमाचल दौरे के दौरान पर भी इस विषय पर विस्तार से चर्चा हुई। आयोग से भी सुझाव आया है कि जहां बच्चों की संख्या कम है, ऐसे स्कूलों को मर्ज किया जाना चाहिए। सरकार के ध्यान में यह मामला पहले से ही है। स्कूलों में एनरोलमेंट में भी कमी आई है। बीते वर्ष भी दो या दो से कम विद्यार्थी संख्या वाले स्कूलों को मर्ज किया गया था। जहां बच्चों की संख्या दो या दो से कम है, ऐसे करीब 700-800 स्कूलों को मर्ज किया जाएगा। प्रथम चरण में उन्हीं स्कूलों को चिन्हित करेंगे, जिनकी अधिक बच्चों की संख्या वाले स्कूल से दूरी डेढ़ से दो किलोमीटर है। शिक्षा निदेशालय इस संबंध में प्रारूप तैयार कर रहा है, जल्द निर्णय लेंगे।

• पहल...

टौर के पत्तल में लंगर

शिमला : ऐतिहासिक मंदिर तारादेवी में 14 जुलाई रविवार से लंगर हरी पत्तल में श्रद्धालुओं को परोसा जाएगा। डीसी अनुपम कश्यप ने जानकारी देते हुए कहा कि अपनी संस्कृति और धरोहर को सहेजने की दिशा में संतुलित पर्यावरण के लिए मंदिरों में टौर के पत्तों से तैयार पत्तल में लंगर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि जिला ग्रामीण विकास प्राधिकरण के आधीन राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत सुन्नी खंड में कार्य कर रहे सक्षम क्लस्टर लेवल फेडरेशन को ये पत्तल बनाने का जिम्मा दिया गया है। उन्हें प्रथम चरण में पांच हजार पत्तल बनाने का ऑर्डर दिया गया है। उक्त फेडेरशन में 2900 से अधिक महिलाएं पत्तल बनाने का काम करती है, लेकिन पत्तलों की डिमांड कम होने के कारण उत्पादन अधिक नहीं करते थे। इस दिशा में अब प्रशासन ने फैसला लिया है कि जिला के सभी मंदिरों में हरी पत्तल में लंगर परोसे जाएंगे। ऐसे में प्रथम चरण में तारादेवी मंदिर से शुरूआत की जा रही है।

• उद्योग समिति की बैठक...

शिमला : प्रदेश में सेब सीजन शुरू हो चुका है ऐसे में शिमला जिला की कृषि बागवानी व उद्योग समिति की एक महत्वपूर्ण बैठक शिमला में आयोजित की गई। बैठक में सेब सीजन के दौरान उचित व्यवस्था बनाने और बागवानों की विभिन्न समस्याओं को लेकर विस्तृत चर्चा की गई। इस बैठक में केंद्र और प्रदेश सरकार के विभिन्न बागवानी योजनाओं को जमीनी स्तर पर अधिक सफल बनाने, सेब सीजन के दौरान मंडियों और सड़कों की उचित व्यवस्था सुनिश्चित करने और बागवानों को यूनिवर्सल कार्टन से संबंधित आ रही दिक्कतों को लेकर विस्तृत चर्चा हुई।